

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एन० 14.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, बोरवार, 1 अक्तूबर, 1987/9 आश्विन, 1909

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 अक्तूबर, 1987

क्रमांक एल० एल० आर० (डी) (6) 8/86-लैजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 30 सितम्बर, 1987 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश सम्पत्ति अधिग्रहण अध्यादेश, 1987 (1987 का अध्यादेश संख्यांक 7) को संविधान

1936

असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अक्टूबर, 1987/9 आश्विन, 1909

---

के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित राजपत्र,  
हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,  
राज कुमार महाजन,  
सचिव (विधि)।

1987 का अध्यादेश संख्यांक 7.

## हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अध्यादेश, 1987

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

राज्य के प्रयोजनों के लिए स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण करने या स्थावर सम्पत्ति के अधिग्रहण के जारी रहने का उपबंध करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिन के कारण उन के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ;

और इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के अनुदेश प्राप्त कर लिए गए हैं ;

अतः अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश बनाते और प्रख्यापित करते हैं:—

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अध्यादेश, 1987 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह जुलाई, 1983 के अट्ठाईसवें दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

संक्षिप्त  
नाम,  
विस्तार  
और  
प्रारम्भ ।

2. इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —

परिभाषाएं ।

(क) “अधिनिर्णय” से धारा 9 के अधीन मध्यस्थ द्वारा दिया गया कोई अधिनिर्णय अभिप्रेत है ;

(ख) “सक्षम प्राधिकारी” से सरकार द्वारा, इस अध्यादेश के अधीन ऐसे क्षेत्र के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के पालन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) “सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(घ) “भूस्वामी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय किसी परिसर का, चाहे अपने वास्ते या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते या उसकी ओर से, या उसके फायदे के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में किराया प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है, या जो इस प्रकार किराया प्राप्त करता या किराया प्राप्त करने का हकदार होता, यदि परिसर किसी अभिधारी को किराए पर दिए गए होते ;

(ङ) “शासकीय राजपत्र” से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;

(च) किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में “हितवद् व्यक्ति” पद के अन्तर्गत, इस अध्यादेश के अधीन उस सम्पत्ति के अधिग्रहण के कारण संदेय प्रतिकर में

हित का दावा करने वाले या दावा करने के हकदार सभी व्यक्ति हैं ;

(छ) "परिसर" से कोई इमारत या इमारत का भाग अभिप्रेत है ; और

(i) ऐसी इमारत या इमारत के भाग से संबन्धित उद्यान, मैदान और उपगृह, यदि कोई हों, और

(ii) ऐसी इमारत या इमारत के भाग के अधिक फायदाप्रद उपयोग के लिए उस में की गई कोई फिटिंग, उसके अन्तर्गत हैं :—

(ज) "विहित" से इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "सम्पत्ति" से हर प्रकार की स्थावर सम्पत्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति में या उसके बारे में अधिकार हैं ;

(ञ) "अभिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिस द्वारा या जिसकी ओर से किन्हीं परिसरों का किराया संदेय है और इसके अन्तर्गत ऐसे उप-अभिधारी और अन्य व्यक्ति हैं जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अभिधारी के अधीन हक व्युत्पन्न हुआ है ।

स्थायर  
सम्पत्ति  
अधिग्रहण  
करने की  
शक्ति ।

3. (1) जहां सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि कोई सम्पत्ति किसी लोक प्रयोजन के लिए, जो राज्य का प्रयोजन है, आवश्यक है या आवश्यक होनी सम्भाव्य है, और सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, तो सक्षम प्राधिकारी—

(क) स्वामी या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से जिस का सम्पत्ति पर कब्जा हो, लिखित नोटिस द्वारा, (उसमें अधिग्रहण का प्रयोजन विनिर्दिष्ट करते हुए) ऐसे नोटिस की उस पर तामील होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि सम्पत्ति क्यों अधिगृहीत, नहीं की जानी चाहिए ; और

(ख) आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि ना ही सम्पत्ति का स्वामी और ना ही कोई अन्य व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना, सम्पत्ति का व्ययन करेगा या उसमें संरचनात्मक परिवर्तन करेगा, या अभिधारी को किराए पर देगा, जब तक कि दो मास से अनधिक ऐसी अवधि का अवसान नहीं हो जाता, जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) यदि सम्पत्ति में हितवद्ध या उस सम्पत्ति पर कब्जा रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बताया गए हेतुक पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह, लिखित आदेश द्वारा, सम्पत्ति का अधिग्रहण कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा जो अधिग्रहण के सम्बन्ध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा सम्पत्ति या उसका भाग का,—

(क) जो उसके स्वामी द्वारा वास्तव में अपने या कुटुम्ब के निवास के रूप में प्रयोग की जाती है, या



(ख) जो या तो जनता द्वारा अनन्यतः धार्मिक पूजा के लिए या पाठशाला, अस्पताल, लोक पुस्तकालय या अनाथालय के रूप में या ऐसे धार्मिक स्थान या ऐसी पाठशाला, अस्पताल, पुस्तकालय या अनाथालय के प्रबन्ध से सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा वास सुविधा के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है,

अधिग्रहण नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि जहाँ अधिग्रहित सम्पत्ति ऐसे परिसर से मिलकर बनी है, जिन का प्रयोग अभिधारी, द्वारा, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील की तारीख से ठीक पूर्व दो मास से अन्यून अवधि के लिए निवास के रूप में किया जा रहा है, वहाँ सम्पत्ति पर कब्जा तब तक नहीं लिया जायेगा जब तक सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे अभिधारी के लिए ऐसी आनुकूलिक वास-सुविधा की व्यवस्था नहीं कर दी जाती जो उसकी राय में उपयुक्त हो।

4. (1) जहाँ धारा 3 के अधीन कोई सम्पत्ति अधिगृहीत की गई है, सक्षम प्राधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा स्वामी और किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका सम्पत्ति पर कब्जा हो, उस सम्पत्ति का, सक्षम प्राधिकारी को या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर कब्जा, अर्पणित या परिदत्त करने का आदेश दे सकेगा।

अधिगृहीत सम्पत्ति का कब्जा लेने की शक्ति।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन दिये गये आदेश का अनुपालन करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी सम्पत्ति का कब्जा ले सकेगा और, उस प्रयोजन के लिए, ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हो।

(3) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का कब्जा लेने पर, सक्षम प्राधिकारी, धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर की रकम के बारे में किसी करार के अभाव में और इस अध्यादेश के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी सम्पत्ति के लिए अन्तिम प्रतिकर के रूप में, स्वामियों या उसके हकदार व्यक्तियों को उस द्वारा प्राक्कलित किराए के अस्सी प्रतिशत का प्रतिमास संदाय, निविदत्त करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन संदत्त या निविदित रकम को, धारा 9 के अधीन संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रतिकर की रकम का अवधारण करने के लिए, हिसाब में लिया जायेगा और जहाँ इस प्रकार संदत्त प्रतिकर धारा 9 के अधीन अवधारिता प्रतिकर से अधिक हो, अधिक्य जब तक अधिनिर्णय की तारीख से तीन मास के भीतर प्रतिदाय न किया जाये, तत्पश्चात् संदेय किराए में से कटौती द्वारा वसूलीय होगा।

5. (1) धारा 3 के अधीन अधिगृहीत समस्त सम्पत्ति का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अधिग्रहण नोटिस में उल्लिखित किए जाएं।

अधिगृहीत सम्पत्ति पर अधिकार।

(2) जहाँ धारा 3 के अधीन कोई परिसर अधिगृहीत किये गए हैं सक्षम प्राधिकारी भू-स्वामी को यह आदेश दे सकेगा कि वह ऐसी मुरम्मत जैसी आवश्यक हो और उस परिक्षेत्र में भू-स्वामियों द्वारा प्रायः की जाती है और जो नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, युक्तियुक्त

समय के भीतर करेगा जैसा उसमें उल्लिखित किया गया है और यदि भू-स्वामी ऐसे आदेश के अनुसरण में किन्हीं मुरम्मतों को करने में असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी आदेश में विनिर्दिष्ट मुरम्मत को भू-स्वामी के खर्चे पर करवा सकेगा, और उसकी लागत की कटौती, वसूली के किसी ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भू-स्वामी को देय प्रतिकर में से की जा सकेगी।

अधिग्रहण  
से  
निर्मुक्त।

6. (1) सक्षम प्राधिकारी इस अध्यादेश के अधीन अधिगृहीत किसी सम्पत्ति को किसी भी समय निर्मुक्त कर सकेगा और सम्पत्ति को यथा साध्य उतनी अच्छी हालत में, जितनी में वह उस समय थी, जब उस का कब्जा लिया गया था, केवल युक्तियुक्त टूट-फूट और अप्रतिरोध्य शक्ति द्वारा कारित परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, प्रत्यावातित करेगा :

परन्तु जहां वे प्रयोजन, जिनके लिए किसी अधिगृहीत सम्पत्ति का प्रयोग किया जा रहा था, अस्तित्वहीन हो जाते हैं, सक्षम प्राधिकारी, यथाशीघ्र, सम्पत्ति को अधिग्रहण से निर्मुक्त करेगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार—

(क) हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1972 के अधीन अधिगृहीत किसी सम्पत्ति को जिसका कब्जा अभी तक सरकार के पास है, जुलाई, 1983 के 28वें दिन से दस वर्ष की अवधि के अवसान पर या उससे पूर्व;

1973 का  
20

(ख) 1983 की जुलाई के 27वें दिन के पश्चात् इस अध्यादेश के अधीन, अधिगृहीत या अधिगृहीत समझी जाने वाली किसी सम्पत्ति को, उस तारीख से जिसकी ऐसी सम्पत्ति का कब्जा सक्षम प्राधिकारी को धारा 4 के अधीन अभ्यर्पित या परिदत्त किया गया था या उसके द्वारा लिया गया था, दस वर्ष की अवधि के अवसान पर या उसके पूर्व,

अधिग्रहण से निर्मुक्त करेगी।

(3) जहां कोई सम्पत्ति अधिग्रहण से निर्मुक्त की जानी है, सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसी वह किसी मामले में करना या कराना आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसको सम्पत्ति का कब्जा दिया जायेगा और ऐसा कब्जा, यथासाध्य, उस व्यक्ति को जिससे अधिग्रहण के समय कब्जा लिया गया था या ऐसे व्यक्ति के हित-उत्तराधिकारियों को, दिया जाएगा।

(4) उप-धारा (2) के अधीन किसी आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को सम्पत्ति के कब्जे का परिदान, उस सम्पत्ति के बार में सरकार को समस्त दायित्वों से उन्मोचन होगा किन्तु यह उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति के किन्हीं अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जिन्हें कोई वह विधि की सम्यक् प्रक्रिया द्वारा इस व्यक्ति के विरुद्ध प्रवृत्त कराने का हक्दार है, जिसको सम्पत्ति का कब्जा दिया जाता है।

(5) जहां कोई व्यक्ति, जिस को अधिगृहीत सम्पत्ति का कब्जा दिया जाना है उपलब्ध नहीं है उसकी ओर से कोई अभिकर्ता या कोई व्यक्ति परिदान स्वीकार करने के लिए सशक्त नहीं है, वहां सक्षम प्राधिकारी एक नोटिस, यह घोषित करते हुए कि

सम्पत्ति अधिग्रहण से निर्मुक्त की जाती है, सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाया गया और राजपत्र में भी नोटिस प्रकाशित करायेगा।

(6) जब उप-धारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, तब ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति ऐसे प्रकाशन की तारीख को और से अधिग्रहण के अधीन नहीं रह जायेगी और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उस का परिदान उस व्यक्ति को किया गया है जो उसके कब्जे का हकदार है और सरकार उस तारीख के पश्चात् किसी भी अवधि के लिए उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(7) जहां इस अध्यादेश के अधीन अधिगृहीत कोई सम्पत्ति या उस का कोई महत्वपूर्ण भाग अग्नि, भूचाल, आंधी, बाढ़ या किसी सेना की संक्रिया या भीड़ द्वारा हिंसा या अन्य अप्रतिरोध्य बल के कारण सम्पूर्णतः नष्ट हो जाता है या सारतः और स्थायी रूप से उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए उसे अधिगृहीत किया गया था, अनुपयुक्त हो जाता है, वहां सरकार के विकल्प पर अधिग्रहण शून्य होगा :

परन्तु इस उप-धारा का फायदा सरकार को उपलब्ध नहीं होगा जहां ऐसी सम्पत्ति को क्षति, सरकार के दोषपूर्ण कार्य या व्यक्तिगत से हुई हो।

7. (1) किसी सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात्, सम्पत्ति का स्वामी या ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति, अधिग्रहण से इसकी निर्मुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा :

अधिग्रहण से निर्मुक्त के लिए आवेदन।

परन्तु ऐसा आवेदन सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से दो वर्ष के अवसान से से पूर्व किया जाएगा यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों जिन पर स्वामी या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति, धारा (3) की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन दिए कारण बताने के लिए दिए गए अवसर पर, जोर नहीं दे सका।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर सक्षम प्राधिकारी, स्वामी या सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति से, ऐसी जानकारी मंगाने पर जैसी आवश्यक पाई जाये या ऐसी और जांच करने पर जैसी वह आवश्यक समझे उस के सम्बन्ध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह उचित समझे।

8. धारा 7 के अधीन अधिग्रहण से निर्मुक्त के लिए आवेदन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामंजूर किए जाने और धारा 12 के अधीन राज्य सरकार के मक्ष दाखिल अपील के भी नामंजूर किए जाने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मुक्ति के लिए अगला आवेदन दो वर्ष की अवधि के अवसान तक, ग्रहण नहीं किया जाएगा :

अधिग्रहण से निर्मुक्ति के लिए अतिरिक्त आवेदन।

परन्तु स्वामी या सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, प्रथम अपील की नामंजुरी के दो वर्ष के भीतर दूसरा आवेदन किया जा सकेगा यदि आगे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों जिन पर पूर्ववर्ती आवेदन में जोर नहीं दे सका हो।

9. (1) जहां इस अध्यादेश के अधीन कोई सम्पत्ति अधिगृहीत की जाए, वहां प्रतिकर संदत्त किया जाएगा जिस की राशि इस में इसके पश्चात् उपवर्णित रीति और

प्रतिकर अवधारित करने के

सिद्धांत और सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी ;  
पद्धति । अर्थात्:—

- (क) जहां प्रतिकर की राशि करार द्वारा निश्चित की जाए, यह उस ऐसे करार के अनुसार संदत्त की जाएगी ;
  - (ख) जहां ऐसा कोई करार नहीं हो सकता है वहां सरकार ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थता के रूप में नियुक्त करेगी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उस रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित है ;
  - (ग) सरकार किसी विशिष्ट मामले में, ऐसे व्यक्ति को, जिसको अधिगृहीत सम्पत्ति की प्रकृति के बारे में विशेषज्ञीय जानकारी प्राप्त है, मध्यस्थ की सहायता के लिए नामनिर्दिष्ट कर सकेगी और जहां ऐसा नामनिर्देशन किया जाता है वहां वह व्यक्ति जिसे प्रतिकारित किया जाना है, उसी प्रयोजन के लिए किसी असेसर को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ;
  - (घ) मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों के प्रारम्भ पर, सरकार और वह व्यक्ति जिस को प्रतिकारित किया जाना है, यह बताएंगे कि उनकी अपनी-अपनी राय में प्रतिकर की उचित रकम क्या है ;
  - (ङ) मध्यस्थ, विवाद की सुनवाई के पश्चात् धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए सम्पत्ति अधिग्रहण आदेश की तारीख से, संगणित एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रतिकर की रकम को, जो उसे न्यायसंगत प्रतीत होती है, अवधारित करते हुए और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनको ऐसा प्रतिकर संदत्त किया जायेगा, अधिनिर्णय देगा और अधिनिर्णय देते समय वह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को और इस धारा की उप-धारा (2) के उपबन्धों को, ध्यान में रखेगा ;
  - (च) जहां उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के बारे में विवाद है जो प्रतिकर के हकदार हैं, मध्यस्थ ऐसे विवाद का विनिश्चय करेगा और यदि मध्यस्थ को यह मालूम होता है कि एक से अधिक व्यक्ति प्रतिकर के हकदार हैं, तो वह रकम को ऐसे व्यक्तियों में प्रभारित करेगा ;
  - (छ) मध्यस्थम अधिनियम, 1940 की कोई भी बात इस अधिनियम के अधीन मध्यस्थता को लागू नहीं होगी । 1940 का 10
- (2) किसी सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए देय प्रतिकर की रकम उप-धारा (3) और (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—
- (क) अधिग्रहण की अवधि की वास्तविक इतनी आवृत्ति राशि का संदाय जितनी उस किराए के बराबर है जो इस सम्पत्ति के उपयोग और अधिभोग के लिए उस दशा में देय होती यदि वह सम्पत्ति उस अवधि के लिए पट्टे पर ली गई होती ; और

(ख) ऐसी राशि या राशियां, यदि कोई हों, जो निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी मामले में हितवद्ध किसी व्यक्ति को प्रतिकारित करने के लिए आवश्यक पाई जाएं, अर्थात्—

- (i) अधिग्रहण के कारण हुई धनीय हानि ;
- (ii) अधिगृहीत परिसरों को खाली करने का व्यय ;
- (iii) अधिग्रहण से निर्मुक्त होने पर परिसर का पुनः अधिभोग लेने में व्यय ; और
- (iv) अधिग्रहण अवधि के दौरान सम्पत्ति को साधारण टूट-फूट से अन्यथा हुई नुकसानी, जिसके अन्तर्गत वह व्यय भी है जो सम्पत्ति को उस दशा में प्रत्यावर्तित करने में उपगत करना पड़े, जिस में वह अधिग्रहण के समय थी ।

(3) किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उप-धारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवर्ती संदाय, जब तक सम्पत्ति धारा 6 के अधीन अधिग्रहण से शीघ्र ही निर्मुक्त नहीं की जाती, उप-धारा (4) के उपबन्धों के अनुसार पुनरीक्षित किया जायेगा ;

(क) ऐसी दशा में जहां सम्पत्ति, इस अध्यादेश के प्रारम्भ से ठीक पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए या उससे अधिकतर अवधि के लिए अधिग्रहण के अधीन रही हो—

- (i) पहली बार ऐसे प्रारम्भ की तारीख से, और
- (ii) पुनः ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष के अवसान की तारीख से ;

(ख) ऐसी दशा में जिसमें ऐसी सम्पत्ति ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व पांच वर्ष से न्यूनतर अवधि के लिए अधिग्रहण के अधीन रही हो और अधिकतम अवधि जिस में धारा 6 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार ऐसी सम्पत्ति अधिग्रहण से निर्मुक्त की जाएगी, पांच वर्ष से अधिक न हो इसके अधिग्रहण की तारीख से :—

(i) पहली बार ऐसी सम्पत्ति के कब्जे को अभ्यर्पित या परिदत्त करने या सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 4 के अधीन लेने की तारीख से पांच वर्ष के अवसान की तारीख से ; और

(ii) पुनः खण्ड (1) के अधीन किए गये पुनरीक्षण के प्रभावी होने से पांच वर्ष की अवधि के अवसान की तारीख से ;

(ग) किसी अन्य दशा में, ऐसी सम्पत्ति के कब्जे को अभ्यर्पित या परिदत्त करने या सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 4 के अधीन लेने की तारीख से पांच वर्ष के अवसान की तारीख से ।

(4) किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में आवर्ती संदाय, ऐसे संदाय की उप-धारा (2) के खण्ड (क) साथ पठित उप-धारा (1) में उपबणित रीति और सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित करके, पुनरीक्षित किया जाएगा, मानों कि ऐसे सम्पत्ति इस अध्यादेश के अधीन उस तारीख को अधिगृहीत की गई थी जिस तारीख से उप-धारा (3) के अधीन पुनरीक्षण किया जाता है ।

(5) जहाँ प्रतिकर में अनेक व्यक्ति हितबद्ध हैं, सरकार के लिए स्वप्रेरणा से या उस में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर विवाद की बाबत अधिनिर्णय या अनुपूर्वक अधिनिर्णय देने के लिए उसे या किसी अन्य मध्यस्थ को नियुक्त करना विधिपूर्ण होगा।

स्पष्टीकरण.—उप-धारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करते समय कोई अवधि या अवधि जिनके दौरान किसी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी रोक या व्यादेश के कारण कार्यवाहियां रोक दी गई हों, अपवर्जित की जाएंगी।

प्रतिकर  
का संदाय।

10. (1) किसी अधिनिर्णय के अधीन देय प्रतिकर की रकम सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए उसके हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को, ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर जो निनिर्दिष्ट किया जाए, संदत्त की या दी जाएगी।

(2) प्रतिकर की रकम या उसके किसी भाग पर ब्याज धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिग्रहण के आदेश की तारीख से रकम के संदत्त या निविदत्त किए जाने की तारीख पर्यन्त 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संदेय होगा :

परन्तु जहाँ ऐसा प्रतिकर या उस का कोई भाग इसके देय होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संदत्त या निविदत्त नहीं किया जाता, वहाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए ब्याज 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संदेय होगा :

स्पष्टीकरण 1.—इस उप-धारा के अधीन ब्याज की संगणना के लिए, धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन अन्तिम प्रतिकर के रूप में संदत्त रकम, यदि अधिनिर्णय देते समय घटाई न गई हो तो, अधिनिर्णय के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम में से कटौती की जाएगी।

स्पष्टीकरण 2.—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उस के लिए हकदार व्यक्तियों को प्रतिकर की रकम को निविदत्त किया जाना, इस अध्यादेश के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय समझा जाएगा।

अधिग्रहण  
के आदेश  
से अपील।

11. (1) धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए अधिग्रहण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर सरकार को अपील कर सकेगा :

परन्तु सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हुआ था, उक्त इक्कीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, सरकार सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट मंगाने के पश्चात् और पक्षकारों को सुनवायी का अवसर देने और ऐसी अतिरिक्त जांच यदि कोई हो, करने के पश्चात् जैसी आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसे वह उचित समझे और सरकार के आदेश अन्तिम होंगे।

(3) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन अपील की जाए, सरकार सक्षम प्राधिकारी के आदेश का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर रोक सकेगी जैसी वह उचित समझे।

12. (1) धारा 7 और 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर, सरकार को अपील कर सकेगा :

परन्तु सरकार, यदि इसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हुआ था, उक्त इक्कीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट मंगाने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जैसी यह आवश्यक समझे, ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जैसे वह उचित समझे और सरकार के आदेश अन्तिम होंगे।

13. (1) धारा 9 के अधीन किए गये मध्यस्थ के अधिनिर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अधिनिर्णय की तारीख से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में अपील कर सकेगा :

परन्तु उच्च न्यायालय यदि इसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त हेतुक से समय पर अपील दाखिल करने से निवारित हुआ था, तो वह उक्त 30 दिन की अवधि के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) यदि वह राशि, जो उच्च न्यायालय की राय में, मध्यस्थ द्वारा प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णित की जानी चाहिए थी उस राशि से अधिक हो जो मध्यस्थ ने प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णित की है, तो उच्च न्यायालय निदेश दे सकेगा कि सक्षम प्राधिकारी ऐसी अधिक राशि पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन अधिग्रहण के आदेश की तारीख से ऐसी अधिक राशि के संदत्त या निविदत्त किए जाने की तारीख प्रयन्त, नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदत्त करेगा :

परन्तु उच्च न्यायालय यह निदेश भी दे सकेगा कि जहाँ ऐसी अधिक राशि या उस का कोई भाग धारा (3) की उप-धारा (2) के अधीन अधिग्रहण के आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान की तारीख के पश्चात् संदत्त या निविदत्त किया जाता है, वहाँ ऐसी अधिक राशि की रकम पर या उस के भाग पर, जो अवसान की ऐसी तारीख से पूर्व संदत्त या निविदत्त नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त अवधि के अवसान की तारीख से, 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

स्पष्टीकरण:—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस के लिए हकदार व्यक्तियों को प्रतिकर की रकम का निविदत्त किया जाना, इस अध्यादेश में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए विधिमान्य संदाय समझा जाएगा।

अधिग्रहण से निम्नित्त के लिए आवेदन को नामंजूर करने के सक्षम प्राधिकारी के आदेश से अपील।

प्रतिकर सम्बन्धी अधिनिर्णय से अपील।

सक्षम  
प्राधिकारी  
और  
मध्यस्थ को  
सिविल  
न्यायालयों  
की कतिपय  
शक्तियों का  
प्राप्त होना।

14. सक्षम प्राधिकारी और धारा 9 के अधीन नियुक्त मध्यस्थ को, इस अध्यादेश के अधीन, यथास्थिति, जांच या मध्यस्थ कार्यवाही करते समय, निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय इसे प्राप्त होती है, अर्थात्:—

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा कराना ;
- (ख) किसी दस्तावेज को प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;
- (ग) साक्ष्य का शपथ पर लिया जाना ,
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना ;
- (ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

जानकारी  
अभिप्राप्त  
करने की  
शक्ति।

15. सरकार या सक्षम प्राधिकारी, धारा 3 या धारा 6 या धारा 9 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, आदेश द्वारा किसी व्यक्ति से ऐसे अधिकारी को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, अपने पास की ऐसी जानकारी को देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो इस अध्यादेश के अधीन अधिगृहीत या अधिगृहीत की जाने के लिए आशयित किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट की जाए।

प्रवेश और  
निरीक्षण  
करने की  
शक्ति।

16. सक्षम प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशक्त कोई अधिकारी यह अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए किसी सम्पत्ति में प्रवेश कर सकेगा और उस का निरीक्षण कर सकेगा, कि क्या ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में या इस अध्यादेश के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, कोई आदेश दिया जाना चाहिए और यदि किया जाना है, तो किस रीति में।

नोटिस और  
आदेश की  
तामील।

17. (1) इस धारा और किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जो इस अध्यादेश के अधीन बनाये जाएं, इस अध्यादेश के अधीन जारी किया गया या दिया गया प्रत्येक नोटिस या आदेश,—

- (क) साधारण स्वरूप या किसी वर्ग या व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले किसी नोटिस या आदेश की दशा में राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ; और
- (ख) किसी व्यष्टिक, निगम या फर्म को प्रभावित करने वाले किसी नोटिस या आदेश की दशा में, उसकी तामील, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची क, यथास्थिति, आदेश के नियम 2 या आदेश के नियम 3 में समन की तामील के लिए उपबंधित रीति से की जाएगी ; और
- (ग) किसी व्यष्टिक व्यक्ति (जो निगम या फर्म नहीं है) को प्रभावित करने वाले नोटिस या आदेश की दशा में, उसकी तामील ऐसे व्यक्ति पर—

(i) इसे उस व्यक्ति को परिदत्त या निविदत्त करके ; या



(ii) यदि इसे इस प्रकार उसे परिदत्त या निविदत्त नहीं किया जा सकता है, तो इसे ऐसे व्यक्ति के किसी अधिकारी या कुटुम्ब के किसी व्यक्ति पुरुष सदस्य को परिदत्त या निविदत्त करके या उसकी एक प्रति उस परिसर के, जिसके बारे में यह ज्ञात है कि उसमें उस व्यक्ति ने अन्तिम बार निवास किया है, या कारबार किया है या व्यक्तिगत रूप से अभिलाषों के लिए कार्य किया है, बाह्य द्वार या किसी सहज दृश्य मांग पर लगा कर; या

(iii) इन साधनों द्वारा तामील करने में असफल रहने पर, डाक द्वारा की जाएगी।

(2) जहां सम्पत्ति का स्वामित्व विवादग्रस्त है या जहां सम्पत्ति में हितवद्ध व्यक्तियों का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता हो और नोटिस या आदेश की तामील असम्यक् विलम्ब के बिना नहीं की जा सकती हो, नोटिस या आदेश की तामील इसे राजपत्र में प्रकाशित करके, और जहां सम्भव हो, उस सम्पत्ति के जिससे इसका सम्बन्ध है, किसी सहजदृश्य भाग पर उसकी एक प्रति लगा कर, की जा सकेगी।

18. इस अध्यादेश के अधीन अधिगृहीत या अर्जित किसी सम्पत्ति में हितवद्ध कोई व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित सम्पत्ति के बिना या मुरम्मत करने या नगरपालिका की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के प्रयोजनों के सिवाय, जानबूझ कर ऐसी सम्पत्ति से संलग्न सुविधा या सुखाचार में विघन नहीं डालेगा या उसके साथ स्थायी उपयोग के लिए दी गई किसी वस्तु को न हटाएगा, न नष्ट या बेकार करेगा और न ही सम्पत्ति के लिए दिए गए प्रदाय या सेवा को बन्द करेगा या बन्द करवाएगा।

सुखाचारा  
में विघन  
न डालना।

19. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि धारा 11, 12 और 24 के अधीन के सिवाय, इस अध्यादेश के अधीन इस द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, सरकार के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी।

शक्तियों का  
प्रत्यायोजन।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई सभी अधिसूचनाएं, यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखी जाएंगी।

20. (1) इस अध्यादेश या तदधीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन, या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

सद्भाव-  
पूर्वक की  
गई कार्रवाई  
के लिए  
संरक्षण।

(2) सरकार या सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध इस अध्यादेश या तदधीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई या होने के लिए सम्भाव्य किसी नुकसानी के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध न होगी।

21. इस अध्यादेश में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी न्यायालय को, किसी ऐसे मामले में जिससे सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ, इस अध्यादेश द्वारा या इसके अधीन अवधारण के लिए सशक्त है, अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी, और इस अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली कार्रवाई के लिए किसी न्यायालय द्वारा व्यादेश मंजूर नहीं किया जायेगा।

सिविल  
न्यायालयों  
की अधि-  
कारिता का  
वर्जन।

अपराधों के लिए शास्ति।

22. जो कोई भी इस अध्यादेश या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या इस अध्यादेश के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा या इस अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में बाधा डालेगा, वह जर्मनि से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, और जब अपराध निरन्तर हो, तब अतिरिक्त जर्मनि से, जो प्रथम अपराध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिस के दौरान अपराध निरन्तर रहता है, पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक होना।

23. सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक मध्यस्थ और सरकार द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा सशक्त प्रत्येक अधिकारी, इस अध्यादेश के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का पालन करते समय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

1860 का  
45.

नियम बनाने की शक्ति।

24. (1) सरकार, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

- (क) धारा 3 या धारा 6 के अधीन जांच करने में समक्ष प्राधिकारों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;
- (ख) इस अध्यादेश के अधीन मध्यस्थ कार्यवाहियों और अपीलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;
- (ग) प्रतिकर की रकम अवधारित करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत, संदाय का ढंग और ऐसे प्रतिकर की शर्तें ;
- (घ) इस अध्यादेश के अधीन मध्यस्थ के समक्ष और अपील में कार्यवाहियों की लागत के प्रभाजन में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत ;
- (ङ) नोटिस और आदेशों के तामील की रीति ;
- (च) किराया और इस की वसूली,
- (छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है। यदि उस सत्र के जिस में उसे इस प्रकार रखा गया है या उपर्युक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है, तो तत्पश्चात् वह उस परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान से पूर्व

विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से इस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

25. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी—

स्थावर  
सम्पत्तियों  
के कतिपय  
अधिग्रहण  
का विधि-  
मान्यकरण।

1973 का 20

(i) हिमाचल प्रदेश अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1972 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिगृहीत कोई स्थावर सम्पत्ति (उस अधिनियम के अधीन अधिगृहीत समझी गई किसी सम्पत्ति सहित) जो ऐसे अधिग्रहण से जुलाई, 1983 के 28वें दिन से पूर्व निर्मुक्त नहीं की गई है ;

1973 का 20

(ii) हिमाचल प्रदेश रिक्वीजिशनिंग ऐण्ड एक्वीजिशनिंग ऐक्ट, 1972 के अधीन सरकार के किसी अधिकारी द्वारा जुलाई, 1983 के 28वें दिन के पश्चात् अधिगृहीत की गई आशयित कोई स्थावर सम्पत्ति और जो ऐसे अधिग्रहण से निर्मुक्त नहीं की गई है ;

ऐसे अधिग्रहण का तारीख से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन, उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए उक्त सम्पत्ति अधिगृहीत या धारित की गई थी, अधिगृहीत की गई समझी जाएगी और इस अध्यादेश के सभी उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिग्रहण की, किसी भी :  
के संदाय के लिए अवधारण और अधिनिर्णय के लिए सभी  
प्रतिकर का सम्बन्ध है, विधिमान्य होंगे और सदैव विधिमान्य रहे सम  
प्रवृत्त रहेंगे तथा उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रतिकर के संदाय को ल

तकर  
भावी  
न्तर

26. (1) किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त सरकार द्वारा बनाए जाएं, किसी अधिगृहीत सम्पत्ति की बाबत किराए के रूप में कोई देय राशि जो बकाया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, संदाय के लिए दायी व्यक्ति से उसी रीति में वसूल की जाएगी जिसमें भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।

अनुगृहीत  
सम्पत्ति  
सम्बन्धी  
किराए और  
नुकसानी  
को भू-  
राजस्व की  
बकाया के  
रूप में वसूल  
करने की  
शक्ति।

(2) जहां कोई व्यक्ति किसी, अधिगृहीत सम्पत्ति के अप्राधिकृत अधिभोग में है, सक्षम प्राधिकारी, विहित रीति में, उक्त सम्पत्ति के प्रयोग और अधिभोग के कारण हुई नुकसानी का निर्धारण कर सकेगा, जैसे वह उचित समझे और, डाक द्वारा ऐसी अन्य रीति में, जैसी इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, तामील नोटिस द्वारा उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, नुकसानी का संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (2) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नुकसानी का संदाय करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, तो नुकसानी

1950

असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अक्तूबर, 1987/9 आश्विन, 1909

---

उसी रीति में वसूल की जाएगी जिसमें भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है ।

आर० कें० एस० गांधी,  
राज्यपाल,  
हिमाचल प्रदेश ।

शिमला :  
30 सितम्बर, 1987

राज कुमार महाजन,  
सचिव (विधि),  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

*[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Sthavar Sampatti Adhigrahan Adhyadesh, 1987 (1987 Ka Adhyadesh Sankhyank-7) as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

Ordinance No. 7 of 1987

## THE HIMACHAL PRADESH REQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY ORDINANCE, 1987

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Thirty-eighth Year of the Republic of India.

An Ordinance to provide for the requisition of immovable property of the continuance of requisition of immovable property for purposes of the State.

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

And whereas instruction of the President of India to promulgate this Ordinance have been obtained;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make and promulgate the following Ordinance:—

1. (1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Requisition of Immovable Property Ordinance, 1987.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on the 28th day of July, 1983.

Short title,  
extent and  
commence-  
ment.

2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) “award” means any award of an arbitrator made under section 9;

(b) “competent authority” means any person or authority authorised by the Government, by notification in the Official Gazette, to perform the functions of the competent authority under this Ordinance for such area as may be specified in the notification;

(c) “Government” means the Government of Himachal Pradesh;

(d) “landlord” means any person, who for the time being is receiving or is entitled to receive the rent of any premises, whether on his own account, or on account or on behalf or for the benefit of any other person or as a trustee, guardian or receiver for any other person or who would so receive the rent or be entitled to receive the rent if the premises were let to a tenant;

(e) “Official Gazettee” means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(f) the expression “person interested” in relation to any property includes all persons claiming or entitled to claim an interest in the compensation payable on account of the requisition of that property under this Ordinance;

(g) “premises” means any building or part of a building and includes—

(i) the garden, grounds and out-houses, if any pertaining to such building or part of the building; and

(ii) any fittings affixed to such building or part of the building for more beneficial enjoyment thereof;

(h) "prescribed" means prescribed by rules made under this Ordinance;

(i) "property" means immovable property of every kind and includes any rights in or over such property;

(j) "tenant" means any person by whom or on whose account rent is payable for any premises and includes such sub-tenants and other persons as have derived title under the tenant under any law for the time being in force.

Power to  
requisition  
immovable  
property.

3. (1) Where the competent authority is of the opinion that any property is needed or is likely to be needed for any public purpose, being a purpose of the State, and that the property should be requisitioned, the competent authority:—

(a) shall call upon the owner or any other persons who may be in possession of the property, by notice in writing (specifying therein the purpose of the requisition), to show cause, within fifteen days of the date of the service of such notice on him, as to why the property should not be requisitioned; and

(b) may, by order, direct that neither the owner of the property nor any other person shall, without permission of the competent authority dispose of, or structurally alter, the property or let it out to a tenant until the expiry of such period, not exceeding two months as may be specified in the order.

(2) If, after considering the cause, if any, shown by any person interested in the property or in possession thereof, the competent authority is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may, by order in writing, requisition the property and may make such further orders as appear to it to be necessary or expedient in connection with the requisition:

Provided that no property or part thereof—

(a) which is *bona fide* used by the owner thereof as the residence of himself or his family;

(b) which is exclusively used either for religious worship by the public or as a school, hospital, public library or an orphanage or for the purpose of accommodation of a person connected with the management of such place of worship or such school, hospital, library or orphanage,

shall be requisitioned:

Provided further that where the requisitioned property consists of premises which are being used as a residence by a tenant for not less than two months immediately preceding the date of the service of notice under subsection (1), possession of the property shall not be taken unless the competent authority has provided such tenant with alternative accommodation which in its opinion is suitable.

4. (1) Where any property has been requisitioned under section 3, the competent authority may, by notice in writing, order the owner as well as any other person who may be in possession of the property to surrender or deliver possession thereof to the competent authority or any person duly authorised by it in this behalf within thirty days of the service of the notice.

Power to take possession of requisitioned property.

(2) If any person refuses or fails to comply with an order made under sub-section (1), the competent authority may take possession of the property and may, for that purpose, use such force as may be necessary.

(3) On taking possession of any property under this section, the competent authority shall, in the absence of an agreement as to the amount of compensation under clause (a) of sub-section (1) of section 9 and without prejudice to other provisions of this Ordinance, tender every month payment of eighty per centum of rental as estimated by him, as provisional compensation for such property, to the owners or persons entitled thereto.

(4) The amount paid or tendered under sub-section (3), shall be taken into account for determining the amount of compensation required to be paid under section 9 and where the compensation so paid exceeds the compensation determined under section 9, the excess, unless refunded within three months from the date of award, shall be recoverable by deduction from the rental payable thereafter.

5. (1) All property requisitioned under section 3, shall be used for such purposes as may be mentioned in the notice of requisition.

Rights over requisitioned property.

(2) Where any premises are requisitioned under section 3, the competent authority may order the landlord to execute such repairs as may be necessary and are usually made by landlords in that locality and as may be specified in the notice within such reasonable time as may be mentioned therein and if the landlord fails to execute any repairs in pursuance of such order, the competent authority may cause the repairs specified in the order to be executed at the expense of the landlord and the cost thereof may, without prejudice to any mode of recovery, be deducted from the compensation payable to the landlord.

6. (1) The competent authority may at any time release from the requisition any property requisitioned under this Ordinance and shall, as far as possible restore the property in as good condition as it was when possession thereof was taken subject only to the changes caused by reasonable wear and tear and irresistible force:

Release from requisition.

Provided that where the purposes for which any requisitioned property was being used cease to exist, the competent authority shall release the property, as soon as may be, from requisition.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government shall release from requisition—

(a) any property requisitioned under the Himachal Pradesh Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1972, the possession of which is still with the Government, on or before the expiry of a period of ten years from the 28th day of July, 1983;

- (b) any property requisitioned or deemed to be requisitioned under this Ordinance after the 27th day of July, 1983, on or before the expiry of a period of ten years from the date on which possession of such property was surrendered or delivered to, or taken by, the competent authority under section 4.
- (3) where any property is to be released from requisition, the competent authority may, after such enquiry, if any, as it may in any case consider necessary to make or cause to be made, specify by order in writing, the person to whom possession of the property shall be given and such possession shall, as far as practicable, be given to the person from whom possession was taken at the time of the requisition or to the successor(s)-in-interest of such person.
- (4) The delivery of possession of the property to the person specified in an order under sub-section (2) shall be a full discharge of the Government from all liability in respect of the property, but shall not prejudice any rights in respect of the property to which any other person may be entitled, by due process of law, to enforce against the person to whom possession of the property is given.
- (5) Where any person to whom possession of any requisitioned property is to be given is not traceable and has no agent or other person empowered to accept delivery on his behalf, the competent authority shall cause a notice, declaring that the property is released from requisition, to be affixed on some conspicuous part of the property and shall also publish the notice in the Official Gazette.
- (6) When a notice referred to in sub-section (5) is published in the Official Gazette, the property specified in such notice shall cease to be subject to requisition on and from the date of such publication and shall be deemed to have been delivered to the person entitled to possession thereof and the Government shall not be liable for any compensation or other claim in respect of the property for any period after the said date.
- (7) Where any property requisitioned under this Ordinance or any material part thereof is wholly destroyed or rendered substantially and permanently unfit for the purpose for which it was requisitioned by reason of fire, earthquake, tempest, flood or operation of any army or violence of any mob or other irresistible force, the requisition shall, at the option of the Government, be void:

Provided that the benefit of this sub-section shall not be available to the Government where the injury to such property is caused by any wrongful act or default of the Government.

Application  
for release  
from re-  
quisition.

7. (1) After a period of two years from the date of requisition of any property, the owner or any person interested in such property, may apply to the competent authority to release it from requisition:

Provided that such application may be made before the expiry of two years from the date of requisition of the property if circumstances have arisen which the owner or any person interested in the property could not have urged when



given an opportunity to show cause under clause (a) of sub-section (1) of section 3.

(2) On receipt of an application under sub-section (1) the competent authority may, after calling for such information as it may find necessary, from the owner or any person interested in the property or making such further inquiry as it may consider necessary, pass orders in respect of that as it deems fit.

8. After the application for release from requisition made under section 7 has been rejected by the competent authority and the appeal filed before the Government under section 12 has also been rejected, no further application for release will be entertained by the competent authority till the expiry of a further period of two years:

Further application for release from requisition.

Provided that another application may be made by the owner or any person interested in the property within two years of rejection of the first appeal if any further circumstances have arisen which he could not have urged in his previous application.

9. (1) Where any property is requisitioned under this Ordinance, there shall be paid compensation the amount of which shall be determined in the manner and in accordance with the principles hereinafter set out, that is to say—

Principles and methods of determining compensation.

- (a) Where the amount of compensation is fixed by agreement who it shall be paid in accordance with such agreement;
- (b) where no such agreement can be reached, the Government shall appoint as an arbitrator a person who is, or has been or is qualified for appointment as, a Judge of a High Court;
- (c) the Government may, in any particular case, nominate a person having expert knowledge as to the nature of the property requisitioned to assist the arbitrator and where such nomination is made, the person to be compensated may also nominate an assessor for the same purpose;
- (d) at the commencement of the proceedings before the arbitrator, the Government and the person to be compensated shall state what in their respective opinion is a fair amount of compensation;
- (e) the arbitrator shall, after hearing the dispute, make an award, within a period of one year reckoned from the date of order of requisition made by the competent authority under sub-section (2) of section 3, determining the amount of compensation which appears to him to be just and specifying the person or persons to whom such compensation shall be paid; and in making the award, he shall have due regard to the circumstances of each case and the provisions of sub-section (2) of this section;
- (f) where there is any dispute as to the person or persons who is/are entitled to the compensation, the arbitrator shall decide such dispute and if the arbitrator finds that more than one person is entitled to compensation, he shall apportion the amount thereof amongst such persons;

10 of 1940. nothing in the Arbitration Act, 1940 shall apply to arbitration under this section.

(2) The amount of compensation payable for the requisition of any property shall subject to the provisions of sub-sections (3) and (4), consist of—

- (a) a recurring payment, in respect of the period of requisition of a sum equal to the rent which would have been payable for the use and occupation of the property, if it had been taken on lease for that period; and
- (b) such sum or sums, if any, as may be found necessary to compensate the person interested in all or any of the following matters, namely:—
  - (i) pecuniary loss due to requisition;
  - (ii) expenses on account of vacating the requisitioned premises;
  - (iii) expenses on account of re-occupying the premises upon release from requisition; and
  - (iv) damages (other than normal wear and tear) caused to the property during the period of requisition, including the expenses that may have to be incurred for restoring the property to the same condition in which it was at the time of requisition.

(3) The recurring payment, referred to in clause (a) of sub-section (2), in respect of any property shall, unless the property is sooner released from requisition under section 6, be revised in accordance with the provisions of sub-section (4),—

- (a) in a case where such property has been subject to requisition for a period of five years or a longer period immediately preceding the commencement of this Ordinance—
  - (i) in the first instance with effect from the date of such commencement, and
  - (ii) further with effect from the expiry of five years from such commencement;
- (b) in a case where such property has been subject to requisition immediately before such commencement for a period shorter than five years and the maximum period within which such property shall, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 6, be released from requisition, extends beyond five years from the date of its requisition,—
  - (i) in the first instance with effect from the date of expiry of five years from the date on which possession of such property has been surrendered or delivered to, or taken by, the competent authority under section 4, and
  - (ii) further with effect from the date of expiry of a period of five years from the date on which the revision made under clause (i) takes effect;

(c) in any other case, with effect from the date of expiry of five years from the date on which possession of such property has been surrendered or delivered to, or taken by, the competent authority under section 4.

(4) The recurring payment in respect of any property shall be revised by re-determining such payment in the manner and in accordance with the principles set out in sub-section (i) read with clause (a) of sub-section (2), as if such property had been requisitioned under this Ordinance on the date with effect from which the revision has to be made under sub-section (3).

(5) Where there are several persons interested in the compensation, it shall be lawful for the Government either on its own motion or on an application from any person interested therein, to appoint the same or any other arbitrator to make an award or supplementary award in respect of the disputes.

*Explanation.*—In computing the period referred to in clause (a) of sub-section (1), any period or periods during which proceedings are held up on account of any stay or injunction by an order of any court, shall be excluded.

10. (1) The amount of compensation payable under an award shall, subject to any rules made under this Ordinance, be paid or given by the competent authority to the person or persons entitled therein in such manner and within such time as may be specified.

Payment of  
compensa-  
tion.

(2) An interest at the rate of 9 percentum per annum shall be payable on the amount of compensation or any part thereof from the date of order of requisition made by the competent authority under sub-section (2) of section 83 till the date the amount stands paid or tendered:

Provided that where such compensation or part thereof is not paid or tendered within one year from the date it becomes due, interest at the rate of 15 percentum per annum shall be payable for the period exceeding one year.

*Explanation I.*—For computing interest under this sub-section, the amount paid as provisional compensation under sub-section (3) of section 4, is not already reduced while making the award, shall be deducted from the amount of compensation payable under the award.

*Explanation II.*—For the removal of doubts it is clarified that tender of amount of compensation to the persons entitled thereto shall, without prejudice to other provisions of this Ordinance, be deemed to be the payment of compensation to the persons interested therein, for the purposes of this sub-section.

11. (1) Any person aggrieved by an order of requisition made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 may, within twenty one days from the date of service of the order, prefer an appeal to the Government:

Appeal from  
order of  
requisition.

Provided that the Government may entertain the appeal after expiry of the said period of twenty-one days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the Government may, after calling for a report from the competent authority and giving an opportunity to the parties of being heard and after making such further enquiry if any, as may be necessary, pass such orders as it thinks fit and the orders of the Government shall be final.

(3) Where an appeal is preferred under sub-section (1), the Government may stay the enforcement of the order of the competent authority for such period and on such conditions as it thinks fit.

Appeal  
from order  
of compe-  
tent autho-  
rity  
rejecting  
application  
for release  
from re-  
quisition.

12. (1) Any person aggrieved by an order made by the competent authority under sections 7 and 8 may, within twenty-one days from the date of service of the order, prefer an appeal to the Government:

Provided that the Government may entertain the appeal after the expiry of the said period of twenty-one days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the Government may, after calling for a report from the competent authority and after making such further inquiry as it may consider necessary, pass such orders as it deems fit and the orders of the Government shall be final.

Appeal  
from award  
in respect  
of compen-  
sation.

13. (1) Any person aggrieved by an award of the arbitrator made under section 9 may, within thirty days from the date of such award prefer an appeal to the High Court of Himachal Pradesh:

Provided that the High Court may entertain the appeal after expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) If the sum which, in the opinion of the High Court, the arbitrator ought to have awarded as compensation is in excess of the sum which the arbitrator did award as compensation, the High Court may direct that the competent authority shall pay interest on such sum in excess at the rate of 9 per centum per annum from the date of the order of requisition made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 till the date the amount of such sum in excess stands paid or tendered:

Provided that the High Court may also direct that where such sum in excess or any part thereof is paid or tendered after the date of expiry of a period of one year from the date on which the order of requisition is made under sub-section (2) of section 3, interest at the rate of 15 per centum per annum shall be payable from the date of expiry of the said period of one year on the amount of such sum in excess or part thereof which has not been paid or tendered before the date of such expiry.

*Explanation.*—For the removal of doubts it is clarified that tender of a amount of compensation to the persons entitled there to without prejudice to the provisions contained in this Ordinance, shall be deemed to be valid payment for the purposes of this sub-section.

14. The competent authority and the arbitrator appointed under section 9, while holding an inquiry or arbitration proceedings, as the case may be, under this Ordinance, shall have all powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely:—

Competent authority and arbitrator to have certain powers of civil courts.

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) reception of evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record from any court or office; and
- (e) issuing commissions for examination of witnesses.

15. The Government or the competent authority may, with a view to carrying out the purposes of section 3 or section 6 or section 9 by order require any person to furnish to such officer, as may be specified in the order, such information in his possession as may be specified relating to any property which is requisitioned or intended to be requisitioned under this Ordinance.

Power to obtain information.

16. The competent authority or any officer, empowered in this behalf by such authority by general or special order, may enter and inspect any property for the purposes of determining whether and if so in what manner an order under this Ordinance should be made in relation to such property or with a view to securing compliance with an order made under this Ordinance.

Power to enter and inspect.

17. (1) Subject to the provisions of this section and any rules that may be made under this Ordinance, every notice or order issued or made under this Ordinance shall,—

Service of notice and order.

- (a) in case of any notice or order of a general nature or affecting a class of persons, be published in the official gazette;
- (b) in case of any notice or order affecting an individual, corporation or firm,

5 of 1908. be served in the manner provided for the service of summons in rule 2 of order XXIX or Rule 3 of Order XXX, as the case may be, in the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908; and

- (c) in the case of any notice or order affecting an individual person (not being a corporation or firm) be served on such person—

- (i) by delivering or tendering it to that person; or
- (ii) if it cannot be so delivered or tendered, by delivering or tendering it to any officer of such person or any adult male member of the family of such person, or by affixing a copy thereof on the outer door or on some conspicuous part of the premises in which that person is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain; or

- (iii) failing service by these means, by post.

(2) Where the ownership of the property is in dispute or where the persons interested in the property are not readily traceable and the notice or

order cannot be served without undue delay, the notice or order may be served by publishing it in the official Gazette, and where possible, by affixing a copy thereof on any conspicuous part of the property to which it relates.

Easement  
not to be  
disturbed.

18. No person interested in any property requisitioned or acquired under this Ordinance shall, without the previous written consent of the competent authority or except for the purpose of affecting repairs or complying with municipal requirement, willfully disturb any convenience or easement attached to such property or remove, destroy or render unserviceable anything provided for permanent use therewith or discontinue or cause to be discontinued any supply or service provided for the property.

Delegation  
of powers.

19. (1) The Government may, by notification in the official Gazette, direct that the powers except those under sections 11, 12 and 24 exercisable by it under this Ordinance shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the notification, be exercisable also by an officer subordinate to that Government.

(2) All notifications issued under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before the Legislative Assembly.

Protection  
of action  
taken in  
good faith.

20. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Ordinance or any order made thereunder.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Government or the competent authority for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Ordinance or any order made thereunder.

Bar of  
jurisdiction  
of civil  
courts.

21. Save as otherwise expressly provided in this Ordinance, no civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the competent authority or arbitrator is empowered by or under this Ordinance to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Ordinance.

Penalty for  
offences.

22. Whoever contravenes any provision of this Ordinance or any rule made thereunder or any order made or direction given under this Ordinance or obstructs the lawful exercise of any power conferred by or under this Ordinance shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees, and when the offence is a continuing one with a further fine which may extend to fifty rupees for every day after the first during which the offence continues.

Certain  
persons to  
be public  
servants.

23. The competent authority, every arbitrator and every officer empowered by the Government or by the competent authority, while exercising any power or performing any duty under this Ordinance, shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

24. (1) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

Power to make rules.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the procedure to be followed by the competent authority in making inquiries under section 3 or section 6;
- (b) the procedure to be followed in arbitration proceedings and appeals under this Ordinance;
- (c) the principles to be followed in determining the amount of compensation, method of payment and conditions of such compensation;
- (d) the principles to be followed in apportioning the cost of proceedings before the arbitrator and an appeal under this Ordinance;
- (e) the manner of service of notices and orders;
- (f) rent and its recovery; and
- (g) any other matter which has to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule framed under this Ordinance, shall be laid as soon as may be after it is made before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session, in which it is so laid or the sessions aforesaid, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

25. Notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force—

Validation of certain requisitions of immovable properties.

- (i) any immovable property requisitioned by the competent authority under the Himachal Pradesh Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1972 (including any property deemed to have been requisitioned under that Act) which had not been released from such requisition before the 28th day of July, 1983);
- (ii) any immovable property which purports to have been requisitioned, after the 28th day of July, 1983, by an Officer of the Government, under the Himachal Pradesh Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1972, and which has not been released from such requisition;

shall, as from the date of such requisition, be deemed to have been requisitioned by the competent authority under the provisions of this Ordinance for the purposes for which the said property was requisitioned or held and all provisions of this Ordinance shall apply accordingly:

Provided that all agreements for determination and awards for payment of compensation in respect of any such property for any period of requisition shall be binding in so far as future compensation is concerned shall be valid and shall be deemed always to have been valid and shall continue to be in force and shall apply to payment of compensation in respect of that property.

Power to  
recover  
rent or  
damages in  
respect of  
requisition-  
ed property  
as arrears  
of land  
revenue.

26. (1) Subject to any rule that may be made in this behalf by the Government, any sum due by way of rent in respect of any requisitioned property which is in arrears may be recovered by the competent authority from the persons liable to pay the same in the same manner as an arrear of land revenue.

(2) Where any person is in unauthorised occupation of any requisitioned property, the competent authority may, in the prescribed manner, assess such damages on account of the use and occupation of the said property as it thinks fit and may, by notice served by post or in such other manner, as may be prescribed by rules made in this behalf, order that person to pay the damages within such time as may be specified in the notice.

(3) If any person refuses or fails to pay the damages within the time specified in the notice under sub-section (2), damages may be recovered in the same manner as arrears of land revenue.